



सामग्य जपने

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 377]

नई दिल्ली, वीरवार सितम्बर 18, 1986/भाद्र 27, 1908

No. 377]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 18, 1986/BHADRA 27, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1986

आदेश

स्टाम्प

का. आ. 677 (अ).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) का धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा वित्त मंत्रालय (राजस्व तथा बीमा विभाग) के दिनांक 16 मार्च, 1976 के का. आ. 199 (अ.) में निहित भारत सरकार के आदेशों में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उपर्युक्त आदेश में निहित परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“बशर्ते कि ऊपर उल्लिखित स्टाम्प शुल्क की दरें निम्नलिखित स्वीतों में पूँजी के आहरण अथवा प्राप्त करने के लिए वित्तिय-पत्रों अथवा प्रामिनिरी नोटों की अवधि पर लागू नहीं होगी :—

- (1) भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, राज्य वित्त निगमों, वाणिज्यिक बैंकों तथा सहाकारी बैंकों से निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए लेने पर :—

(क) प्रामाणिक वाणिज्यिक अथवा व्यापारिक लेन-देनों के लिए,

(ख) आवश्यक कृषि प्रचालनों अथवा फसल के विपणन के लिए, अथवा

(ग) कुटीर तथा लघु उद्योगों के उत्पादन अथवा विपणन कार्यकलापों के लिए ;

- (2) भारतीय निर्यात-आयात बैंक से प्रामाणिक निर्यात-आयात लेन-देनों के लिए और इस प्रकार के दस्तावेजों पर उक्त अनुच्छेद 13 में उपर्युक्त मदों (ख) और (ग) के माध्यम से निर्दिष्ट दरों के 1/5 भाग के अनुसार स्टाम्प शुल्क लगेगा।

स्पष्टीकरण—1 :—परन्तुक के प्रयोजनों के लिए :—

(क) “कृषि प्रचालनों” शब्दावली में पशु-पालन तथा कृषि प्रचालनों के साथ संयुक्त रूप में किए जाने वाले सम्बद्ध कार्यकलाप भी शामिल हैं;

(ख) “फसल” में कृषि-प्रचालनों के उत्पाद भी शामिल हैं;

(ग) “फसल के विपणन” शब्दावली में कृषि उत्पादकों अथवा ऐसे उत्पादकों के किसी संगठन द्वारा फसल के विपणन में पूर्ण उस पर की जाने वाली प्रक्रिया भी शामिल है।

स्पष्टीकरण—2 :—जहाँ कहीं आवश्यक समझा जाएगा, प्रसार्य शुल्क को अगले पांच पैसे तक पूर्णिक में परिवर्तित किया जाएगा।”

[संख्या 39/86—स्टाम्प; फा. सं. 33/62/84-बि. क.]
एल. क. राठोड़, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 18th September, 1986

ORDER

STAMPS

S.O. 677(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. S. O. 199 (E), dated the 16th March, 1976, namely :—

In the said Order, for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

'Provided that the rates of stamp duty mentioned above shall not apply to usance Bills of Exchange or Promissory notes drawn or made for securing finance,—

- (i) from the Reserve Bank of India, Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, State Financial Corporations, Commercial Banks and Co-operative Banks for—

- (a) bona fide commercial or trade transactions,

- (b) seasonal agricultural operations or the marketing of crops, or

- (c) production or marketing activities of cottage and small scale industries;

- (ii) from the Export-Import Bank of India for bona fide export-import transactions;

and such instruments shall bear the rates of stamp duty at one-fifth of the rates specified against the said items (b) and (c) in the said article 13.

Explanation 1.—For the purposes of the proviso—

- (a) the expression "agricultural operations" includes animal husbandry and allied activities jointly undertaken with agricultural operations;
- (b) "Crops" include products of agricultural operations;
- (c) the expression "marketing of crops" includes the processing of crops prior to marketing by agricultural producers of any organisation of such producers.

Explanation 2.—The duty chargeable shall, wherever necessary, be rounded off to the next five paise.'

No. 39/86-Stamps F. No. 33/62/84-ST]

L. K. RATHOD, Director